

प्रेषक,

अतर सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

चिकित्सा अनुभाग-5

देहरादून :

22 जून, 2016

विषय: लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड जनपद टिहरी गढ़वाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहिया जनपद देहरादून सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर जनपद देहरादून एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव जनपद उत्तरकाशी के माह दिसम्बर 2015 तक के बीजकों के भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या सं0-27प/पी०पी०पी०/23/2014/1674 दिनांक 20.01.2016, सं0-27प/पी०पी०पी०/28/2013/1831, दिनांक 21.01.2016, सं0-27प/पी०पी०पी०/21/2013/5794, दिनांक 11.03.2016 एवं सं0-27प/पी०पी०पी०/23/2014/1654 दिनांक 19.01.2016 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक निजी सहभागिता के आधार पर संचालित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र थत्यूड जनपद टिहरी गढ़वाल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सहिया जनपद देहरादून सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रायपुर जनपद देहरादून एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र नौगांव जनपद उत्तरकाशी के माह दिसम्बर 2015 के बीजक क्रमशः ₹12,50,026.00, ₹10,63,763.00, ₹25,73,481.00 एवं ₹ 05,39,504.00 अर्थात् कुल ₹ 54,26,774.00 (चौवन लाख छब्बीस हजार सात सो चौहत्तर मात्र) के भुगतान की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त कर व्यय किये जाने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

1. यह आदेश मा० उच्च न्यायालय नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या-3230/2015 मै० राजभरा मेडिकेयर प्रा० लि० बनाम राज्य एवं अन्य में मा० न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 23.12.2015 के आलोक में निर्गत किये जा रहे हैं। उक्त आदेश मा० न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-3230/2015 एवं रिट याचिका संख्या-71/2016 में मा० न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम आदेश के अधीन रहेंगे।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण कर इसका भुगतान मै० राजभरा मेडिकेयर प्रा० लिमि०, बरेली के साथ निष्पादित अनुबन्ध की शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उक्त संस्था को नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। किसी भी प्रकार के अनियमित भुगतान के लिए महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, देहरादून जिम्मेदार होंगे।
3. निजी सहभागी द्वारा उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में प्रदान की जा रही सेवाओं के संतोषजनक होने के सम्बन्ध में पूर्णतः सुनिश्चित हो लेने के उपरान्त ही धनराशि का भुगतान किया जायेगा। KPI के अनुसार यदि कटौती बनती हो, तो अनुबन्धानुसार धनराशि में कटौती की जानी सुनिश्चित की जायेगी।
4. व्यय करने से पूर्व जिन मामलों मे बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पहले ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।
5. उक्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं महानिदेशक से प्राप्त संस्तुति के आधार पर अवमुक्त की जा रही है।

6. किसी भी शासकीय व्यय हेतु Procurement Rules, 2008 व वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), आय व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7. इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, आयोजनागत, 06-लोक स्वास्थ्य, 101-रोगों का निवारण तथा नियंत्रण 99-राज्य सरकार द्वारा निजी सहभागिता के आधार पर विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों का संचालन, मानक मद 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जायेगा।
8. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-490/XXVII(1)/2016 दिनांक 31.3.2016 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे हैं।

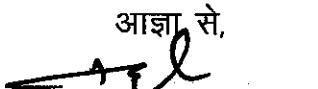
संलग्नक आलॉटमेन्ट आई डी-0-S1606120206

भवदीय,
(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव

संख्या- 392 (1) / XXVIII-5-2016-35 / 2015 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

- 1—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, माजरा देहरादून।
- 2—प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 3—निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 4—मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5—बजट राजकोषीय, नियोजन व संसाधन निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
- 6—वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-३, उत्तराखण्ड शासन।
- 7—नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8—एन०आई०सी०।
- 9—मै० राजभरा मेडिकेयर प्रा०लि०, नई दिल्ली।
- 10—गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अतर सिंह)
संयुक्त सचिव